



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 34]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 23, 2018/माघ 3, 1939

No. 34]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 23, 2018/MAGHA 3, 1939

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 2018

प्रकरण सं. OI-45/2017

विषय - चीन जन. गण., यूरोपीय संघ और यूएसए के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'कोटेड पेपर' के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जाँच की शुरूआत

फा. सं. 6/42/2017-डीजीएडी.—इंडियन पेपर मेनुफैक्चरर्स एसोसिएशन मै. बल्लारपुर इंडस्ट्रीज लि. की सहायक मै. बिल्ट ग्राफिक्स पेपर प्रॉडक्ट्स लि. (जिन्हें आगे याचिकाकर्ता या आवेदक कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे पाटनरोधी नियमावली कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन (जिसे याचिका भी कहा गया है) दायर की है जिसमें चीन जन. गण., यूरोपीय संघ और यूएसए, इंडोनेशिया और कोरिया के मूल के अथवा वहां से निर्यातित

कोटेड पेपर (जिसे आगे संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जाँच की शुरुआत करने का अनुरोध किया है।

2. और यतः प्रथम दृष्टया इस निष्कर्ष पर पहुँचने के बाद कि पाटनरोधी जाँच की शुरुआत को न्यायोचित ठहराने के लिए चीन जन. गण., यूरोपीय संघ और यूएसए (जिन्हें आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल की अथवा वहाँ से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को हुई क्षति तथा कथित पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के साक्ष्य मौजूद हैं, प्राधिकारी एतद्वारा पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अनुसार कथित पाटन और घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति की जाँच की शुरुआत करते हैं ताकि कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की उस राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई 'क्षति' को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

3. प्राधिकारी ने प्रथम दृष्टया पाया कि जाँच अवधि के लिए इंडोनेशिया और कोरिया गणराज्य से संबद्ध वस्तु के आयातों के संबंध में कोई पाटन नहीं हुआ है। तदनुसार, अन्य दो देशों अर्थात् इंडोनेशिया और कोरिया के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित आयातों के संबंध में पाटनरोधी जाँच शुरू नहीं की जा रही है।

क. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

4. वर्तमान याचिका में विचाराधीन उत्पाद 'काओलिन (चाइना क्ले) या कैल्शियम कार्बोनेट या पालीमर या अन्य अकार्बनिक पदार्थ से कोटेड पेपर या पेपर बोर्ड है, बाइंडर सहित या उससे रहित, और किसी एक या दोनों साइडों में किसी अन्य कोटिंग के बिना, चाहें सतह पर रंग हो अथवा नहीं, सतह डेकोरेटेड या मुद्रित हो, रोलों में या आयताकार (वर्गाकार सहित) शीटों में, किसी भी आकार में, चाहें डल हो अथवा नहीं, चमकदार, मेट या हाई-ग्लोस (कास्ट कोटेड फिनिश, जिसे आम तौर पर परंतु विशेष रूप से नहीं कैमिकल पल्प से बनाया जाता है, जो अध्याय 4810 के अधीन उचित ढग से वर्गीकृत है।

5. विचाराधीन उत्पाद का उपयोग प्राथमिक रूप से मैगजीन, कैटेलाॅग, पुस्तकों और पुस्तिकाओं, कैलेण्डरों, ब्रासररों, लेबलों, फ्लेस्विल पैकेजिंग आदि में किया जाता है। कोटेड पेपर के लिए जीएसएम 40 जीएसएमसे 350 जीएसएम के बीच होता है।

6. इस याचिका के दायरे से पैकेजिंग उपयोग के लिए मल्टिलेयर्ड बोर्ड से विशेष रूप से बाहर रखा गया है जो विचाराधीन उत्पाद का हिस्सा नहीं है।

7. वर्तमान जाँच के अधीन सीमाशुल्क शीर्ष 4810 के अधीन आने वाले कोटेड पेपर और पेपर बोर्ड शामिल हैं। तथापि, सीमाशुल्क शीर्ष केवल सांकेतिक हैं और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं हैं।

ख. घरेलू उद्योग और योग्यता

8. यह आवेदन घरेलू उद्योग मै. बिल्ट ग्राफिक्स पेपर प्रॉडक्ट्स की ओर से इंडियन पेपर मेनुफैक्चरर्स एसोसिएशन द्वारा दायर किया गया है, जो संबद्ध वस्तु के उत्पादक हैं। विचाराधीन उत्पाद का एक और ज्ञात घरेलू उत्पादक, जेके पेपर लिमिटेड है। यह देखा जाता है कि याचिकाकर्ता कंपनी द्वारा उत्पादन उत्पादित समान उत्पाद के भारतीय उत्पादन में एक प्रमुख हिस्सा बनता है। यह भी नोट किया जाता है कि याचिकाकर्ता कंपनी ने न तो संबद्ध वस्तु आयात किया है और न ही वह संबद्ध वस्तु के किसी आयातक या निर्यातक से संबंधित है। इस प्रकार, यह निर्धारित किया जाता है कि आवेदन घरेलू उद्योग द्वारा और उसकी ओर से दायर किया गया है और आवेदन पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अधीन योग्यता की अपेक्षाओं को पूरा करता है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता कंपनी पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अनुसार घरेलू उद्योग है।

ग. समान वस्तु

9. आवेदक ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। दोनों उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसे मापदंडों की दृष्टि से तुलनीय विशेषताओं वाले हैं। प्राधिकारी मानते हैं कि वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु के 'समान वस्तु' हैं।

घ. संबद्ध देश

10. उन देशों जिनके विरुद्ध वर्तमान जाँच शुरू की गई है चीन जन. गण., यूरोपीय संघ और यूएसए (वर्तमान अधिसूचना में संबद्ध देश के रूप में संदर्भित) हैं।

ङ. सामान्य मूल्य

चीन जन. गण.

11. चीन और गैर-बाजार अर्थव्यवस्था मानने के संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा किए गए अनुरोधों के संबंध में, प्राधिकारी द्वारा यह नोट किया जाता है कि डब्लूटीओ में चीन द्वारा हस्ताक्षरित एक्सेसन प्रोटोकाल के पैरा 15 (क) (i) के अधीन वचनबद्धता में यह अपेक्षित है कि जाँच के अधीन उत्पादक स्पष्ट रूप से यह दर्शाये कि बाजार अर्थव्यवस्था की दशाएं विनिर्माण के संबंध में समान उत्पाद के उत्पादन के संबंध में उद्योग के लिए प्रचलित हैं। यदि यह सिद्ध हो जाता है कि आयातक डब्लूटीओ सदस्य कीमत तुलनीयता निर्धारित करने में जाँच के अधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों और लागतों का प्रयोग करेगा। इसके अलावा, डब्लूटीओ का अनुच्छेद 2.2.1.1 और भारत के एडी नियमावली में यह अपेक्षित है कि उत्पादक/निर्यातक के वित्तीय रिकार्ड उत्पादन लागत को दर्शाते हैं। अतः निम्नलिखित के संबंध में सूचना और उसके समर्थक साक्ष्य निम्नलिखित दर्शाना अपेक्षित है।

(क) कीमत, लागत, कच्ची सामग्री सहित निविष्टि, प्रौद्योगिकी और श्रम की लागत, उत्पादन, बिक्री और निवेश के संबंध में निर्णय बाजार संकेतकों जो आपूर्ति और मांग को दर्शाते हैं और राज्य के किसी हस्तक्षेप के बिना लिये जाते हैं और क्या प्रमुख निविष्टियों की लागत बाजार मूल्य को पर्याप्त रूप से प्रदर्शित करती है।

(ख) उत्पादन लागत और वित्तीय स्थिति किसी विकृति से प्रभावित नहीं हैं।

(ग) उत्पादक/निर्यातक दिवालिया और संपत्ति कानून के अधीन हैं जो फर्मों के प्रचालन के लिए विधिक निश्चितता और स्थिरता की गारंटी देते हैं।

(घ) विनिमय दर में परिवर्तन बाजार दर पर किये जाते हैं।

जाँच शुरूआत के प्रयोजनार्थ परिकलित सामान्य मूल्य को अपनाया गया है।

ईयू और यूएसए

12. आवेदकों ने अनुरोध किया है कि संबद्ध देशों के घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु की सौदा कीमत के सूचना/साक्ष्य प्राप्त करने के प्रयास किए गए थे, परंतु यह सूचना प्राप्त नहीं हो सकी। अतः आवेदक ने सभी संबद्ध देशों में के लिए सामान्य मूल्य का परिकलन उद्गम के देश में उत्पादन लागत के सर्वोत्तम अनुमानों को बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों और तर्कसंगत लाभ के लिए विधिवत रूप से समायोजित करके, उनके आधार पर किया है। जाँच शुरूआत के लिए इस प्रकार परिकलित सामान्य मूल्य को अपनाया गया है।

च. निर्यात कीमत

13. निर्यात कीमत को डीजीसीआईएंडएस के प्रकाशित आकड़ों के अनुसार प्रस्तावित जाँच अवधि के लिए आयातों की मात्रा और मूल्य पर विचार करते हुए निर्धारित किया गया है। समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, कमीशन, पत्तन व्यय, अंतर्देशीय भाड़े के व्यय, ऋण लागत, गैर वापसी-योग्य वैट (केवल चीन के मामले में) और बैंक प्रभारों जिन्हें

संभवतः भारत को निर्यात करने के लिए निर्यातक द्वारा वहन किया गया हो, के संबंध में कीमत समायोजन किए गए हैं।

छ. पाटन मार्जिन

14. निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए, इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य निर्यात कीमत से अधिक है।

ज. क्षति और कारणात्मक संबंध

15. आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना पर घरेलू उद्योग को हुई क्षति का आकलन करने के लिए विचार किया गया है। आवेदक ने पाटित आयातों की समग्र रूप से और उत्पादन और खपत की दृष्टि से बड़ी हुई मात्रा, कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री और उत्पादन, बिक्री, बाजार हिस्से, लाभ, नकद प्रवाह और निवेश पर आय के अनुसार भारी प्रतिकूल प्रभाव के परिणामस्वरूप कथित पाटन के फलस्वरूप क्षति होने के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग द्वारा उठाई जा रही वास्तविक क्षति के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं जो पाटनरोधी जाँच की शुरूआत को न्यायोचित ठहराते हैं।

झ. जाँच की शुरूआत

16. प्राधिकारी पाते हैं कि संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को हुई क्षति तथा कथित पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के साक्ष्य मौजूद हैं जो कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की उस राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई 'क्षति' को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी निर्धारित करने के लिए पाटनरोधी जाँच की शुरूआत को न्यायोचित ठहराते हैं। तदनुसार, प्राधिकारी एतद्वारा पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अनुसार कथित पाटन और घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति की जाँच की शुरूआत करते हैं।

ञ. जांच अवधि

17. वर्तमान जाँच के लिए जाँच अवधि अप्रैल, 2016 से जून, 2017 (15 महीने) तक की है। क्षति जाँच अवधि पर विचार किया गया है और उसमें 2013-2014, 2014-2015 और 2015-2016 की अवधियों और जाँच अवधि को शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है।

ट. सूचना प्रस्तुत करना

18. संबद्ध देशों में ज्ञात निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावास के जरिए संबद्ध देशों की सरकार, भारत में संबद्ध वस्तु के संबंधित समझे जाने वाले आयातकों व प्रयोक्ताओं को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने और प्राधिकारी को निम्नलिखित पते पर अवगत कराने का अनुरोध किया गया है:

निर्दिष्ट प्राधिकारी
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय,
वाणिज्य विभाग,
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,
5 संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001
Dgad.india@gov.in

19. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जाँच से संगत सूचना संबंधी कोई अनुरोध नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र और पद्धति (जो प्राधिकारी की वेबसाइट (www.dgtr.gov.in) से डाउनलोड किया जा सकता है) से प्रस्तुत कर सकता है।

ठ. समय-सीमा

20. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में अधिसूचना के 2 सप्ताह के भीतर अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और इस जाँच की शुरुआत की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर प्रश्नावली के अपने उत्तर दायर करें तथा घरेलू उद्योग के आवेदन पर और पाटनरोधी उपायों को जारी रखने की आवश्यकता पर अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत करें। सूचना हार्ड प्रतियों तथा साफ्ट प्रतियों में प्रस्तुत की जानी चाहिए।

21. यह नोट किया जाए कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है, तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार, रिकार्ड में "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

ड. गोपनीय/अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

22. यदि प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोधों के किसी भाग के संबंध में गोपनीयता का दावा किया जाता है तो ऐसे मामले में निम्नानुसार दो अलग-अलग सैट (क) गोपनीय रूप से अंकित एक सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि); और (ख). अगोपनीय रूप में अंतिम दूसरा सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि) प्रस्तुत करना होगा। दी गई समस्त सूचना पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए।

23. किसी गोपनीय अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। सभी हितबद्ध पक्षों द्वारा गोपनीय पाठ की दो (2) प्रतियाँ और अगोपनीय पाठ की पाँच (5) प्रतियाँ प्रस्तुत करना जरूरी होगा।

24. गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के लिए में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है और/या ऐसी सूचना का सारांशकरण क्यों संभव नहीं है।

25. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध/रिक्त छोड़ी गई और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।

26. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

27. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा। प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ड. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

28. नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

असहयोग

29. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

सुनील कुमार, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd January, 2018

Case No. OI- 45/2017

Subject: Initiation of Anti-Dumping investigation concerning imports of “Coated Paper” originating in or exported from China PR, European Union & USA.

No. 06/42/2017-DGAD.—Indian Paper Manufacturers Association on behalf of M/s BILT Graphics Paper Products Ltd, subsidiary of M/s Ballarpur Industries Ltd. (hereinafter referred to as ‘petitioner’ or “the applicant”) has filed an application (also referred to as “petition”) before the Designated Authority (hereinafter referred to as the “Authority”) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the ‘Act’) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped articles and for Determination of injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter referred to as the “AD Rules”) for initiation of anti-dumping investigation concerning imports of ‘Coated Paper’ (hereinafter referred to as the “subject goods”) originating in or exported from China PR, European Union & USA, Indonesia and Korea.

2. And whereas, on finding prima facie finds that evidence of dumping of the subject goods, originating in or exported from China PR, European Union & USA (hereinafter as “the subject countries”), injury to the domestic industry and causal link between the alleged dumping and injury exist to justify initiation of an anti-dumping investigation; the Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping, and consequent injury to the domestic industry in terms of Rule 5 of the AD Rules, to determine the existence, degree and effect of alleged dumping and to recommend the amount of antidumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.
3. The Authority has prima facie found absence of dumping on imports of subject goods from Indonesia and Korea RP for the period of investigation. The anti-dumping investigation accordingly is not being initiated concerning imports originating in or exported from other two countries namely Indonesia and Korea RP.

A. Product under consideration and like articles

4. The product under consideration in the present petition is “Paper or Paper Board coated with kaolin (china clay) or calcium carbonate or polymer or other inorganic substance, with or without a binder; and with no other coating, either on one or both sides; whether or not surface-coloured, surface-decorated or printed, in rolls or rectangular (including square) sheets, of any sizes; whether or not dull, gloss, matte or high-gloss(cast coated) finish; made generally, but not invariably or exclusively from virgin chemical pulp, properly classifiable under Chapter 4810”.
5. Product under consideration is primarily used for printing of magazines, catalogues, books & manuals, calendars, brochures, labels, flexible packaging etc. The GSM for Coated Paper ranges from 40 gsm to 350 gsm.

6. Specifically excluded from the scope of this petition is multilayered board for packaging purpose which does not form part of the product under consideration.
7. Coated Paper and Paper Board falling under customs heading 4810 is covered under the present investigation. Customs heading is, however, indicative only and not binding on the scope of product under investigation.

B. Domestic Industry & Standing

8. The application has been filed by Indian Paper Manufacturers Association on behalf of domestic industry, M/s BILT Graphic Paper Products Ltd, which is producer of the subject goods. There is one more known domestic producer of the product under consideration, namely, JK Paper Limited. It is seen that the production by the petitioner company constitutes 'a major proportion' in Indian production of the like product produced. It is also noted that petitioner company has neither imported the subject goods, nor is it related to an importer or exporter of the subject goods. It is, thus, determined that the application has been filed by and on behalf of the domestic industry and the application satisfies the requirements of 'standing' under Rule 5 of the AD Rules. Further, the petitioner company constitutes 'Domestic Industry' in terms of Rule 2(b) of the AD Rules.

C. Like Article

9. The applicant has claimed that there is no known difference in product produced by the applicant and exported from the subject countries. Both products have comparable characteristics in terms of parameters such as physical & chemical characteristics, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification, etc. The Authority considers that the subject goods produced by the domestic industry are like article to the subject goods imported from the subject countries, for the purpose of the present investigation.

D. Subject Countries

10. The countries against which present investigation is initiated are China PR, European Union & USA (referred to as "subject countries" in the present notification).

E. Normal value

China PR

11. With regard to the submissions made by the petitioner regarding treating China as a Non-Market Economy, it is noted by the Authority that the commitments under para 15(a) (i) of the Accession Protocol signed by China with WTO requires that the producers under investigation clearly shows that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product. In event of this being substantiated, the importing WTO member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability. Further Article 2.2.1.1 of WTO and AD Rules of India requires that the financial records of producer/exporter reasonably reflect the production costs. Therefore, information and supportive evidence thereof in respect of the following is required to be provided.
 - a. Decisions in regard to price, cost, input including raw material, cost of technology and labour, output, sales and investment, are made in response to market signal reflecting supply and demand and without significant State interference and whether cost of major inputs substantially reflect market value.
 - b. Production costs and financial situation does not suffer from any distortion.
 - c. The producer/exporter are subject to bankruptcy and property law which guarantees legal certainty and stability for the operation of the firms.
 - d. Exchange rate conversions are carried out at the market rate.For the purpose of initiation the constructed normal value is being adopted.

EU & USA

12. The applicant has submitted that efforts were made to get information/evidence of transaction price of subject goods in the domestic market of subject countries but was not able to get such information. The applicant has therefore constructed normal value for all subject countries on the basis of best estimates of cost of production in the country

origin, duly adjusted for selling, general & administrative costs and reasonable profits. For the purpose of initiation the normal value so constructed is being adopted.

F. Export Price

13. Export Prices have been determined considering volume and value of imports for the proposed period of investigation as per DGCI&S Published data. Price adjustments have been made on account of ocean freight, marine insurance, commission, port expenses, inland freight expenses, credit cost, non-refundable VAT (in case of China only) and bank charges which may have been incurred by the exporter for exporting the material to India.

G. Dumping Margin

14. Considering the normal value and export price determined, there is prima facie evidence that the normal value of the subject goods in the subject countries are higher than the export price.

H. Evidence of Injury and Causal Link

15. Information furnished by the applicant has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The applicant has furnished evidence regarding the injury having taken place as a result of the alleged dumping in the form of increased volume of dumped imports in absolute terms and in relation to production and consumption in India, price undercutting, price underselling and consequent adverse impact in terms of decline in production, sales, market share, profit, cash flow and ROI. There is prima facie evidence of the “material injury” being suffered by the domestic industry caused by dumped imports from subject countries to justify initiation of an antidumping investigation.

I. Initiation of investigation

16. The Authority finds prima facie evidence of dumping of subject goods, originating in or exported from the subject countries; injury to the domestic industry and causal link between alleged dumping and injury, to justify initiation of anti-dumping investigation to determine the existence, degree and effect of alleged dumping and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the ‘injury’ to the domestic industry. Accordingly, the Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping and consequent injury to the domestic industry in terms of Para 5 of the Rules.

J. Period of investigation (POI)

17. The period of investigation for the present investigation is from April 2016 –June 2017 (15 Months). The injury investigation period has been considered and proposed to cover the periods 2013-14, 2014-15 and 2015-16 and the period of investigation.

K. Submission of Information

18. The known exporters in the subject countries, the Government of the subject countries through their embassies in India, the importers and users in India known to be concerned with the product are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address

The Designated Authority,
Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties,
Ministry of Commerce & Industry,
Department of Commerce
4th Floor, Jeevan Tara Building,
5 Parliament Street,
New Delhi -110001.
Dgad.india@gov.in

19. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner (downloadable from the website of the authority at www.dgtr.gov.in) within the time limit set out below.

L. Time limit

20. All interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter within 2 weeks of this notification and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application within forty days (40 days) from the date of publication of this notification. The information must be submitted in hard copies as well as soft copies.
21. It may be noted that if no information is received from an interested party within the prescribed time limit, or the information received is incomplete, the authority may record its findings on the basis of the facts available on record, in accordance with the rules.

M. Submission of Information on Confidential/Non-Confidential basis

22. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire's response/submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page.
23. Information supplied without any confidential marking shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies of the confidential version and of the non-confidential version must be submitted by all the interested parties.
24. For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such Information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.
25. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out /summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, parties submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summarization; a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.
26. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
27. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

N. Inspection of Public File

28. In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

O. Non-cooperation

29. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

SUNIL KUMAR, Addl. Secy. & Designated Authority